हिन्दी पाक्षिक

महानगर स्तंभ

RNI NO. RAJHIN/2017/70561

पृष्ठ संख्या.... 2

❐ वर्ष-8 ❐ अंक-23 जयपुर, रविवार 1 दिसम्बर, 2024 ❐ एक प्रति 5 रुपये ❐ कुल पृष्ठ-4

विश्व एड्स दिवसः लड़ाई अभी बाकी है

विश्व एड्स दिवस, 1988 से प्रति वर्ष 01 दिसंबर को मनाया जा रहा है। यह एचआईवी (ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस)/एड्स (एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लोगों को एकजुट करने तथा महामारी के खिलाफएकजुटता प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। यह सरकारों, संगठनों और समुदायों के लिए इस रोग की वर्तमान चुनौतियों पर प्रकाश डालने तथा इसके रोकथाम, उपचार एवं देखभाल में की गई प्रगति को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस दिन को वैश्विक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य अवलोकनों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जो न केवल जागरूकता फैलाता है बल्कि उन लोगों को भी याद भी करता है जिनकी मौत एचआईवी/एड्स के कारण हुई है। यह स्वास्थ्य सेवाओं तक विस्तारित पहुंच जैसे मील के पत्थर का भी उत्सव मनाता है। एचआईवी जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के बारे में ज्ञान को बढ़ावा देकर, विश्व एड्स दिवस एचआईवी से लड़ने तथा सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज एवं स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त करने के बीच के अभिन्न संबंधों पर प्रकाश डालता है।

2024 का विषय- सही रास्ता अपनाएं- मेरी सेहत, मेरा अधिकार!

विश्व एड्स दिवस 2024 का विषय, सही रास्ता अपनाएंरू मेरी स्वास्थ्य, मेरा अधिकार! है, जो स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच और लोगों को अपने स्वास्थ्य प्रबंधन में सशक्त बनने के महत्व पर बल देता है। यह उन प्रणालीगत असमानताओं को संबोधित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो कमजोर आबादी को एचआईवी के आवश्यक रोकथाम एवं उपचार सेवाएं प्राप्त करने से वंचित करती है। वर्ष 2024 का विषय मानवाधिकारों की भूमिका को उजागर करता है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी लोगों को, उनकी पृष्ठभूमि या परिस्थितियों पर ध्यान दिए बिना, स्वास्थ्य अधिकार प्राप्त हो सके। अधिकार-आधारित दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित करके, 2024 का अभियान समावेशिता को बढ़ावा देने, कलंक को कम करने और एचआईवी/एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के लिए वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है।

भारत की एचआईवी/एड्स महामारी पर प्रतिक्रिया- एक व्यापक दृष्टिकोण

भारत में एचआईवी/एड्स महामारी के खिलाफ लड़ाई 1985 में शुरू हुई। इसे विभिन्न जनसंख्या समूहों एवं भौगोलिक स्थानों में वायरस का पता लगाने के लिए सीरो-सर्वेक्षण के साथ शुरू किया गया। अभियान का प्रारंभिक चरण (1985-1991) एचआईवी मामलों की पहचान, ट्रांसफ्यूजन से पहले रक्त सुरक्षा सुनिश्चित करना और लक्षित जागरूकता उत्पन्न करने पर केंद्रित था। इस अभियान में 1992 में राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम (एनएसपीसी) की शुरूआत के साथ तेजी आई। यह देश में एचआईवी/एड्स से निपटने के लिए एक व्यवस्थित एवं व्यापक दृष्टिकोण की शुरुआत थी। 35 वर्षों में, एनएसपी विश्व के सबसे बड़े एचआईवी/एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों में से एक बन चुका है।

एनएसपीसी चरणों का विकास

एनएसपी के पहले चरण (1992-1999) में जागरूकता फैलाने और रक्त सुरक्षा सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी गई। दूसरे चरण (1999-2007) की शुरुआत के साथ, रोकथाम, पहचान और उपचार के लिए सीधे मध्यवर्तन प्रस्तुत किए गए। राज्यों को प्रभावी कार्यक्रम प्रबंधन क्षमता से युक्त किया गया। तीसरे चरण (2007-2012) में गतिविधियों का प्रमुख विस्तार हुआ, जिसमें विकेंद्रीकृत कार्यक्रम प्रबंधन जिला स्तर तक पहुंचा। चौथे चरण (2012-2017) में पहले के प्रयासों को एकीकृत किया गया, जिसमें सरकारी वित्तपोषण में वृद्धि हुई और कार्यक्रम की स्थिरता सुनिश्चित की गई।

विस्तारित एनएसपी के चौथे चरण (2017-2021) में कई ऐतिहासिक पहलों को शुरू किया गया, जिसमें एचआईवी और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 को पारित करना शामिल है, जो एचआईवी-पॉजिटिव लोगों को समान अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है और उनके खिलाफ भेदभाव को रोकता है। यह अधिनियम सितंबर 2018 में प्रभावी हुआ और इसने एचआईवी (पीएलएचआईवी) से ग्रसित लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए भारत की कानूनी संरचना को मजबूत किया। इस चरण के दौरान, सरकार ने 2017 में टेस्ट और ट्रीट नीति की शुरुआत की, यह सुनिश्चित करते हुए कि एचआईवी से निदान प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को उनके नैदानिक चरण की परवाह किए बिना मुफ्त एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी (एआरटी) प्राप्त हो। पीएलएचआईवी लोग, जिन्होंने उपचार बंद कर दिया, उन्हें फिर से जोड़ने के लिए 2017 में मिशन संपर्क पहल की शुरुआत की गई। 2020-2021 के दौरान, कोविड-19 महामारी ने कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां सामने आईं। हालांकि, एनएपीसी ने कार्यक्रम की समीक्षा, समन्वय और क्षमता निर्माण के प्रयासों को बढ़ाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया। कई महीनों की दवाओं का एकसाथ वितरण करके और सामुदाय-आधारित एआरटी रिफिल जैसी नवाचारों के माध्यम से महामारी के दौरान उपचार सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित की गई।

एनएसपीसी का पांचवां चरण- एचआईवी/एड्स की समाप्ति पर नये सिरे से ध्यान केंद्रित करना

एनएसपी का पांचवां चरण केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में 2021-26 के लिए 15,471.94 करोड़ रुपये की लागत के साथ शुरू किया गया। एनएसपी के पांचवे चरण का उद्देश्य पिछली उपलब्धियों को आगे बढ़ाना और लगातार चुनौतियों का समाधान करना, साथ ही 2010 के आधारभूत मूल्य से 2025-26 तक वार्षिक नए एचआईवी संक्रमण एवं एड्स संबंधित मृत्यु दर में 80 प्रतिषत तक कमी लाना है। इसके अतिरिक्त, एनएसपी के पांचवें चरण का उद्देश्य जोखिम और असुरक्षित आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण एसटीआई/आरटीआई सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देते हुए ऊर्ध्वाधर ट्रांसमिशन का समाप्त करना कि एचआईवी ग्रसित 95 प्रतिषत गर्भवती महिलाओं ने वायरल लोड का दमन किया है। एचआईवी और प्रमुख आबादी के साथ रहने वाले 10: से कम लोग कलंक एवं भेदभाव का अनुभव करें।

निष्कर्ष

विश्व एड्स दिवस 2024 एचआईवी/एड्स की समाप्ति की दिशा में किए जाने वाले कार्यों की याद दिलाता है। एनएसपी का पांचवां चरण और इसके का लाभ उठाते हुए, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के साथ प्रमुख सहयोग की योजना बनाई गई है।

एनएसपी के पांचवें चरण का मुख्य उद्देश्य एचआईवी/एड्स का रोकथाम एवं नियंत्रण-

95 प्रतिषत उच्च जोखिम वाले व्यक्ति तक व्यापक रोकथाम सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। 95-95-95 लक्ष्य की प्राप्ति- एचआईवी पॉजिटिव 95 प्रतिषत लोग अपनी स्थिति से अवगत हों, निदान किए गए 95 प्रतिषत लोगों का उपचार होता रहे और उन रोगियों में से 95 प्रतिषत वायरल दमन प्राप्त करें। यह सुनिश्चित करके ऊर्ध्वाधर ट्रांसमिशन का समाप्त करना कि एचआईवी ग्रसित 95 प्रतिषत गर्भवती महिलाओं ने वायरल लोड का दमन किया है। एचआईवी और प्रमुख आबादी के साथ रहने वाले 10: से कम लोग कलंक एवं भेदभाव का अनुभव करें।

निष्कर्ष

विश्व एड्स दिवस 2024 एचआईवी/एड्स की समाप्ति की दिशा में किए जाने वाले कार्यों की याद दिलाता है। एनएसपी का पांचवां चरण और इसके अधिकार-आधारित दृष्टिकोण के माध्यम से, भारत ने रोकथाम, उपचार एवं देखभाल में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की है। हालांकि, प्रणालीगत असमानताओं और सामाजिक कलंक जैसी चुनौतियों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

इसका विषय सही रास्ता अपनाएं मेरा स्वास्थ्य, मेरा अधिकार! जिसमें समावेशिता को बढ़ावा देने, मानवाधिकारों को बनाए रखने और समान स्वास्थ्य देखभाल पहुंच सुनिश्चित करने का सामूहिक अभियान शामिल है। जैसे-जैसे दुनिया 2030 तक एड्स को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के नजदीक पहुंच रही है, भारत सहयोगात्मक कार्रवाई, नवीन रणनीतियों और स्वास्थ्य समानता के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करता है। संरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करके एवं सफल मध्यवर्तनों को बढ़ावा देकर, भारत एचआईवी/एड्स के खिलाफवैश्विक लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, जो सभी के लिए एक स्वस्थ, कलंक मुक्त भविष्य सुनिश्चित करता है।

- साभार-पीआईबी

एचआईवी/एड्स की वर्तमान स्थिति- एक वैश्विक एवं राष्ट्रीय दृष्टिकोण

एचआईवी/एड्स पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम (यूएनएड्स) द्वारा जारी वैश्विक एड्स अपडेट 2023 के अनुसार, वैश्विक स्तर पर एचआईवी/एड्स से लड़ने में महत्वपूर्ण प्रगति प्राप्त की गई है। भारत जैसे देशों में नए एचआईवी संक्रमण मामलों में कमी आई है, जहां एक मजबूत कानूनी संरचना और बढ़े हुई वित्तीय निवेशों ने 2030 तक एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने के लक्ष्य की प्राप्ति करने की दिशा में प्रगति की है। विशेष रूप से, भारत की पहचान कमजोर आबादी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानूनों को मजबूत बनाने के रूप हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर, भारत एचआईवी अनुमान 2023 रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में 25 लाख से ज्यादा लोग एचआईवी से पीड़ित हैं। इसके बावजूद, देश ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसमें वयस्क एचआईवी प्रसार 0.2 प्रतिषत दर्ज किया गया है और अनुमान है कि वार्षिक रूप से नए एचआईवी संक्रमणों की संख्या 66,400 है, जिसमें 2010 के बाद से 44 प्रतिषत की कमी आयी है। भारत ने 39 प्रतिषत की वैश्विक कमी दर को पीछे छोड़ दिया है, जो निरंतर किए गए मध्यवर्तनों की सफलता को दर्शाता है। 16.06 लाख एचआईवी (पीएलएचआईवी) से पीड़ित लोगों के लिए 725 एआरटी (एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी) केंद्रों के माध्यम से मुफ्त उच्च गुणवत्ता वाले आजीवन उपचार की उपलब्धता (जून 2023 के अनुसार) और 2022-2023 में किए गए 12.30 लाख वायरल परीक्षण भारत द्वारा प्रभावित जनसंख्या के लिए देखभाल सुविधा सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

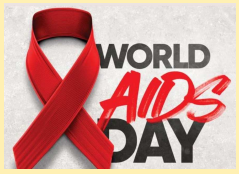

जैसलमेर में खुलेगा देश का पहला कैमल रेस्क्यू रिसर्च सेंटर

जैसलमेर । जैसलमेर में देश का पहला ऊंट रेस्क्यू रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। यहां ऊंटों के स्वास्थ्य को लेकर विशेष काम किया जाएगा। इसको लेकर हाल ही में वेदांता समूह की सहायक टाको अर्गिनाइजेशन ने देगराय ओरण इलाके का दौरा किया और वहां का सर्वे किया। इस दौरान पशु विभाग की टीम व ग्रामीण मौजूद रहे। दरअसल प्रदेश में ऊंटों की घटती संख्या से चिंतित राज्य सरकार जैसलमेर के देगराय ओरण की 100 एकड़ भूमि पर कैमल रेस्क्यू रिसर्च सेंटर को लेकर निर्णय लिया है।

राजस्थान की झांकी 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी खास

तीज की सवारी और हवेलियों से सजेगी राजस्थान की झांकी

रेगिस्तान में हो रही खेती भी दिखाएंगे, दिल्ली में 26 जनवरी की परेड में शामिल होगी

जयपुर। 26 जनवरी 2025 को दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में राजस्थान की झांकी खास है। इस बार झांकी को सोणो राजस्थान% की थीम पर तैयार किया जा रहा है। इसमें तीज माता की सवारी, शेखावाटी की हवेलियां, झरोखे और चित्रकारी दिखाई देगी। साथ ही झांकी को टेक्नोफेंडली बनाते हुए राज्य के विकास को दिखाया जाएगा। केंद्र की तरफ से राजस्थान की झांकी को अप्रूवल मिल गया है। अभी इसकी डिजाइन फाइनल नहीं हुई है। राजस्थान सरकार के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने ललित कला अकादमी को झांकी के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। इस झांकी का निर्माण दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की ओर से अप्रूव एजेंसी की ओर से किया गया है। इसकी डिजाइन और मॉडल जयपुर के वरिष्ठ चित्रकार हरशिव शर्मा बना रहे हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी के सचिव डॉ. रजनीश हर्ष ने बताया- इस बार झांकी के लिए अप्रूवल मिल गई है। इसमें राजस्थान की विरासत और विकास को

अलग तरह से दिखाया जाएगा। इसमें तीज की सवारी से लेकर शेखावाटी की हवेलियां तक भी होंगी।

सबसे आगे होगी तीज माता की सवारी

राजस्थान की झांकी में सबसे आगे तीज माता की सवारी को दिखाया जाएगा। यह जयपुर से जुड़ी होने के कारण त्रिपोलिया गेट और राजशाही से निकलने वाली तीज की सवारी की झलक दिखाएगी। इसे देखने के लिए टूरिस्ट्स पूरी दुनिया से जयपुर पहुंचते है। ऐसे में परेड देखने के लिए मौजूद लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहेगी। इसके बाद कंटेनर पर शेखावाटी की हवेलियां और झरोखे नजर आएंगे। जो कला, संस्कृति और विरासत की खूबसूरती दिखाएगी। यहां हवेलियों पर की गई चित्रकारी भी नजर आएगी।

संपादकीय

हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र

भारत का संविधान ही 140 करोड़ देशवासियों की आत्मा है और डॉ. भीमराव अंबेडकर ही इसकी प्रस्तावना के रचनाकार हैं। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।' डॉ. भीमराव अंबेडकर को इस संविधान के आलोक में याद करते हुए जब हम भारत की खोज को पढ़ते हैं, तो लगता है कि वंदे मातरम् और जन गण मन' जैसी आराधना से बढ़कर कोई अन्य कविता इस धरती पर हो ही नहीं सकती। भारत का यह दिव्य सपना 26 नवंबर, 1949 से हमारे देश का मार्गदर्शक हैदुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधान में वर्णित जो मौलिक अधिकार (1) समानता का अधिकार (2) स्वतंत्रता का अधिकार (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (5) संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार (6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार आज हमें प्राप्त है, उसकी अनुपालना में ही विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका की संपूर्ण संरचना प्रेरित और उत्तरदायी है। इस विभाजीत राष्ट्र की अनेकताओं को एकता में बांधने का यह अमर तंत्र जब डॉ. अंबेडकर ने लिखा था, तब वह कोई दलित नहीं थे, अपितु एक भारतीय नागरिक थे। इसी तरह 1857 से लेकर 1947 तक भारत में जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, उसके सभी महानायक किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग के सैनिक और सेनानी नहीं थे, अपितु भारत के उपासक थे। लेकिन, तब से लेकर अब तक इस देश के विकास और परिवर्तन का प्रवाह कुछ ऐसी विपरीत दिशा में धकेला जा रहा है कि हमने अपने सभी राष्ट्र निर्माताओं को जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्रीयता के हाशिए पर धकेल दिया है। जो भी भारत गणराज्य का अधिपति बनता है, वह एक भारतः श्रेष्ठ भारत और सबका साथ-सबका विकास की नई-नई बातें तो करता है, लेकिन असल में संविधान के विपरीत सत्ता और व्यवस्था का एक नया ताना-बाना भी बुनता है।

राज्यपाल ने हरियाली फैलाने वालों को किया सम्मानित

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि पेड़ पौधों का संरक्षण करके ही पर्यावरण संरक्षण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां पेड़ होते हैं, वहां-वहां बारिश होती है। इसलिए सभी पेड़ लगाएं ही नहीं, उन्हें पानी देकर बचाएं भी। उन्होंने राजस्थान में अमृता देवी द्वारा खेजड़ली में पेड़ों के लिए दिए बलिदान को याद करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन के इस संकट भरे समय में वृक्ष ही मनुष्य के विश्वसनीय मित्र हैं। इससे ही जीवन बच सकता है।

राज्यपाल 30 नवम्बर को श्री कल्पतरू संस्थान द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत ग्रीन आईडल अवार्ड समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि धरती को हरा-भरा करने वाले सभी व्यक्ति सम्माननीय हैं। उन्होंने हरितिमा के लिए कार्य करने वालों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में विश्व का अनूठा एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाया है। इसमें सभी भागीदारी निभाए। उन्होंने वेद-पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में पेड़ पौधों के महत्व की चर्चा करते हुए कहा कि यह वैज्ञानिक तथ्य है कि पेड़ मिट्टी के क्षरण को रोकते हैं। भूमिगत जल भंडारों का पुनर्भरण करते हैं और टिकाऊ कृषि उत्पादन के लिए भी सदा अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। इसलिए पेड़ लगाने के लिए सभी संकल्पबद्ध हों। उन्होंने राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को कल्प वृक्ष बताते हुए देशभर में इसके शमी वृक्ष के रूप में पूजने की परम्परा के बारे में भी विस्तार से बताया।

महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर सच्चिदानंद मुनगंटीवार ने इस अवसर पर देश में वन संस्कृति के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि सभी मिलकर पेड़ लगाएं तो पर्यावरण के साथ मनुष्य की आने वालीं पीढ़ियां के लिए यह सौगात होगी। राज्यपाल ने आरंभ में एक पेड़ मां के नाम के अंतर्गत वृक्ष लगाया। उन्होंने ग्रीन कैंपेन फेर बचपन पोस्टर का भी लोकार्पण किया।

राज्य मंत्री देवासी ने किया कंबल वितरण अभियान का शुभारंभ

जयपुर। मानव आकांक्षा अधिकार अभियान ट्रस्ट के द्वारा सर्दी से बचाव के लिए सिरोही जिले के राजकीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को 5500 कंबल वितरण अभियान का शुभारम्भ 27 नवम्बर को सिरोही नगर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय टांकरिया से किया गया।

मुख्य अतिथि ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज राज्यमंत्री ओटाराम देवासी के कर कमलों से इस अभियान की शुरुआत की गई। मंत्री ने मानव आकांक्षा अधिकार अभियान ट्रस्ट के अध्यक्ष जगदीश पुरोहित को इस पुनीत कार्य के लिए साधुवाद दिया एवं बताया कि ऐसे सेवा और परोपकार की भावना सभी को रखनी चाहिए एवं सदैव सभी के सहयोग के लिए तत्पर रहना चाहिए।

इस दौरान अतिथियों के हाथ से कार्यक्रम में विराजमान सभी छात्र-छात्राओं को कंबल वितरित किए गए और कंबल वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने की उन्होंने अपने संबोधन में अपने ट्रस्ट के माध्यम से जगदीश पुरोहित द्वारा की जा रही सेवा की तारीफ करते हुए उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने इस अवसर पर छात्र-छात्राओं को आगे बढ़ने और सेवा कार्य करते रहने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

कार्यक्रम में आयोजकों ने बताया कि इस अभियान के तहत 50 गांवों की 60 स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार 5500 कंबल वितरित किये जाएंगे। उन्होने बताया कि ट्रस्ट के माध्यम से वे विभिन्न सेवा उपयोगी अभियान चलाते हैं और जरूरतमंदों के लिए घर जाकर सेवा योजना चलाते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिरोही के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। मंच संचालन राकेश पुरोहित ने किया।

राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य पुस्तक के द्वितीय संस्करण का विमोचन

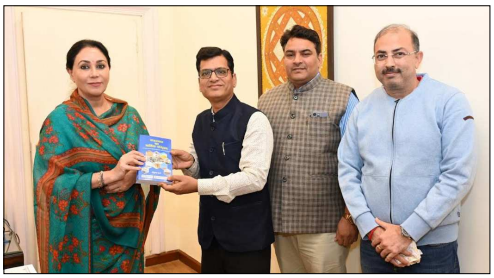

जयपुर। उपमुख्यमंत्री वित्त विभाग दिया कुमारी ने 30 नवम्बर को वित्त विभाग (बजट) के संयुक्त शासन सचिव श्रीकृष्ण शर्मा, द्वारा लिखित पुस्तक ÷राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य÷ के द्वितीय संस्करण का विमोचन किया गया। राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धांतों के साथ साथ व्यावहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर लिखी गई है। जिसे मानक संसाधनों यथा बजट 2024-25, आर्थिक सर्वेक्षण, विभागों के प्रशासनिक प्रतिवेदनों एवं प्रामाणिक सामग्री से तैयार किया गया है। इस अवसर राजस्थान लेखा सेवा के वरिष्ठ अधिकारी भगवान सहाय लाड़ला, वरुण मिश्रा आदि उपस्थित रहे।

सिन्धी समाज के लिए राज्य सरकार का तोहफा

सिन्धु दर्शन यात्रा के लिए मिलेगी 15 हजार रूपए की आर्थिक सहायता

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के आग्रह पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सिन्धी समाज को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सिन्धी समाज की सबसे बड़ी और पवित्र मानी जाने वाली लेह-लद्दाख सिन्धु दर्शन यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 15 हजार रूपए प्रति व्यक्ति आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। सिन्धु दर्शन यात्रा में चार दिन तक लेह-लद्दाख में धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन होते हैं तथा यह यात्रा 18 जून से शुरू होकर 30 जून को समाप्त होती है। सिन्धी समाज के तीर्थयात्री हर साल 23 से 26 जून तक लेह-लद्दाख में सिन्धु दर्शन यात्रा पर जाते हैं। यह यात्रा 18 जून से जम्मू एवं कुरूक्षेत्र से प्रारम्भ होती है तथा 30 जून को इसका अधिकारिक समापन होता है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से आग्रह किया था कि सिन्धु दर्शन तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को भी अन्य तीर्थ यात्राओं की तरह आर्थिक सहायता दी जाए। इस पर निर्णय करते हुए राज्य सरकार ने तीर्थ यात्रियों के लिए 15 हजार रूपए प्रति यात्री की आर्थिक सहायता की घोषणा की है।

गौरतलब है कि वर्ष 1997 में भारत रत्न एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने सिन्धु दर्शन यात्रा की शुरूआत की थी। प्रतिवर्ष यह यात्रा 23 से 26 जून तक लेह-लद्दाख में आयोजित की जाती है। इसमें बड़ी संख्या में सिंधी धर्मावलम्बी भाग लेते हैं। वेद, शास्त्र एवं धार्मिक मान्यताओं में सिन्धु नदी का बड़ा महत्व है। लगभग सभी ग्रन्थों में सिन्धु नदी का उल्लेख मिलता है। इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रगान में भी सिन्धु नदी का उल्लेख है। सिन्धी समाज में भी इष्ट देव श्री झूलेलाल जी के अवतार का जल से संबंध है। ऐसे में यह यात्रा सिन्धी धर्मावलम्बियों के लिए बड़ी पवित्र मानी जाती है। प्रतिवर्ष देश के लगभग 25 राज्यों से सिन्धी धर्मावलम्बी इस पवित्र यात्रा पर जाते हैं। यह यात्रा जम्मू एवं कुरूक्षेत्र से प्रारम्भ होती है एवं लगभग 12 दिन चलती है। यात्रा में लेह-लद्दाख में विशिष्ट धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन होते हैं।

पल्स पोलियो अभियान 8 दिसम्बर को होगा आयोजित

जयपुर। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट टॉस्क फोर्स की बैठक 28 नवम्बर को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में आगामी 8 दिसम्बर पोलियो रविवार को प्रदेश के 39 जिलों में आयोजित होने वाले उप पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों के संबंध में निर्देश दिये गए। प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि सभी संबंधित विभाग पूर्ण समन्वय के साथ तैयारी करते हुए अभियान को सफल बनाएं। बच्चों को आवश्यक रूप से पोलियो की खुराक पिलाए जाने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए एवं आईईसी गतिविधियां की जाएं। एक भी बच्चा पोलियो की खुराक पीने से नहीं छूटे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि प्रदेश में 39 जिलों अजमेर, अलवर, अनूपगढ़, ब्यावर, बांसवाड़ा, बलोतरा, भरतपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, दूदू, डीडवाना-कुचामन, डीग, डूंगरपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर-प्रथम व द्वितीय, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, खैरथल-तिजारा, कोटपुतली-बहरोड़, नागौर, नीम का थाना, फ्लौदी, सांचोर, शाहपुरा, सीकर, सिरोही, सलूम्बर, टोंक एवं उदयपुर में अभियान आयोजित कर जन्म से 5 साल तक की उम्र के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की दवा पिलाई जायेगी। बैठक में निदेशक आईईसी शाहीन अली खान, निदेशक आरसीएच डॉ. सुनीत सिंह राणावत, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग की अतिरिक्त निदेशक अल्का सक्सेना तथा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

भारतीय लोक संस्कृति का विदेशों में प्रचार-प्रसार

संस्कृति मंत्रालय, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को बेहतर बनाने के लिए वैश्विक सहभागिता योजना चला रहा है। इस योजना के तहत, लोगों के बीच संपर्क और द्विपक्षीय सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए विदेशों में भारत महोत्सव (एफओएल) का आयोजन किया जाता है। लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक रंगमंच और कठपुतली, शास्त्रीय तथा पारंपरिक नृत्य, प्रायोगिक और समकालीन नृत्य, शास्त्रीय तथा अर्ध शास्त्रीय संगीत के साथ ही रंगमंच आदि जैसी कलाओं का विविध सांस्कृतिक क्षेत्रों के कलाकार विदेशों में भारत महोत्सव में प्रदर्शन करते हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत-विदेशी मैत्री सांस्कृतिक समितियों को अनुदान सहायता के माध्यम से विदेशों में भारतीय लोक कला, संस्कृति और संगीत को बढ़ावा देता है, जिसके तहत विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों और गतिविधियों के आयोजन के लिए विदेशों में भारत-विदेशी मैत्री सांस्कृतिक समितियों को अनुदान जारी किया जाता है।

2013-14 से 2023-24 के दौरान विभिन्न देशों में कुल 62 भारत महोत्सव आयोजित किए गए हैं। इन भारत महोत्सव में लोक कलाकारों सहित कुल 2348 कलाकारों ने भाग लिया है। भारत महोत्सव में प्रत्येक प्रदर्शन के लिए लोक कलाकारों को 35,000/- रुपये (मुख्य/नेता कलाकार को) तथा 7000/- रुपये (साथी कलाकार को) का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा, संस्कृति मंत्रालय वरिष्ठ कलाकारों के लिए वित्तीय सहायता योजना संचालित करता है जिसका उद्देश्य 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को सहायता प्रदान करना है, जिन्होंने लोक कला सहित कला, साहित्य के विशिष्ट क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है या अभी भी योगदान दे रहे हैं। इस योजना के तहत चयनित कलाकारों को राज्य कलाकारों को मिलने वाली पेंशन की राशि, यदि कोई हो, समायोजित करने के बाद अधिकतम 6000/- रुपये प्रति माह तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

संस्कृति मंत्रालय ने विभिन्न कलाओं के प्रारूपों के अंतर्गत कलाकारों, समूहों को सूचीबद्ध किया है और विदेशों में भारत महोत्सव में प्रदर्शन के लिए सूचीबद्ध नामों वाले कलाकारों का चयन किया जाता है। वर्तमान में, उत्तराखंड के दो लोक कलाकार/समूह और एक कथक कलाकार संस्कृति मंत्रालय के साथ सूचीबद्ध हैं। अब तक उत्तराखंड के एक दल ने 8 से 16 अगस्त, 2017 के दौरान क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य में आयोजित फ्रीडम 70 सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया है। इसके अलावा, वरिष्ठ कलाकारों को वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों और मौजूदा वर्ष में उत्तराखंड राज्य के चार कलाकारों का चयन कर उन्हें सहायता प्रदान की गई है। यह जानकारी केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने 28 नवम्बर को राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में दी।

वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक

हाल ही में, गोल्डमैन सोनेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, इजराइल की बेन-गुरियन यूनिवर्सिटी ऑफ द नेगेव और बायोडीबी डॉट कॉम द्वारा पहली बार वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक (एनसीआई) 2024 जारी किया गया। इसमें भारत को कुल 180 देशों में 176वां स्थान दिया गया है, जो भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरे, क्षमता और शासन और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए भारत के मान्यता प्राप्त प्रयासों को कम करके दिखाता है। एनसीआई ने कई संकेतकों के सम्बंध में भारत द्वारा दिए गए आंकड़ों को ध्यान में नहीं रखा है और कई अन्य स्रोतों पर भरोसा किया है जिससे एनसीआई सूचकांक सही नहीं हैं। इसके अलावा, एनसीआई ने जैव विविधता संरक्षण पर वैश्विक सहयोग के साथ-साथ वैश्विक जलवायु परिवर्तन एजेंडे को लेकर इसकी नेतृत्वकारी भूमिका की वकालत करने वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए), मिशन लाइफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस (आईएसए) और कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंस इंफ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) जैसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण मंचों पर भारत की सबको मार्ग दिखाते हुए आगे बढ़ने की भूमिका को पूरी तरह से नजरअंदाज किया है।

जैव विविधता का महत्व

हाल के वर्षों में, भारत ने भूमि प्रबंधन और जैव विविधता के खतरों से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं, जिन्हें एनसीआई तैयार करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है। उदाहरण के तौर पर भारत सरकार ने जैविक विविधता अधिनियम, 2002 को जैविक विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 (बी.डी. अधिनियम) द्वारा संशोधित किया, साथ ही जैविक संसाधनों और उससे जुड़े ज्ञान के संरक्षण, स्थायी उपयोग और पहुंच को विनियमित करने के लिए नए नियम बनाए। यह अधिनियम, जैव विविधता के संरक्षण के लिए बी.डी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत जैव विविधता प्रबंधन समितियों (बीएमसी) का गठन, जैव विविधता विरासत स्थलों की अधिसूचना और खतरे में पड़ी प्रजातियों की अधिसूचना जैसे विभिन्न उपायों को शामिल करता है। ये अधिसूचना, राज्य जैव विविधता बोर्ड्स (एसबीबी) को अधिसूचित प्रजातियों तक पहुंच बनाने और उनके पुनर्वास और संरक्षण के उपाय करने की शक्ति प्रदान करती है।

भूमि प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण में भारत की कुछ प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार हैं-

भारत में 1022 संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनका क्षेत्रफल 178,640 वर्ग किमी है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 5.43 प्रतिशत है।

कुल वन क्षेत्र 2013 के 21.23 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 21.71 प्रतिशत हो गया है।

एफओ के वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020 के अनुसार भारत का वन क्षेत्र 72.16 लाख हेक्टेयर है और दुनिया भर के शीर्ष दस देशों में भारत का स्थान सुरक्षित है।

पूरे भारत में 487 संरक्षित क्षेत्रों के पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र तैयार किए गए हैं।

रामसर स्थलों की संख्या 2014 के 26 से बढ़कर 2024 में 85 हो गई है।

भारत में 55 बाघ अभ्यारण्य हैं और बाघों की आबादी 2014 में 2226 थी जो 2022 में बढ़कर 3682 हो गई।

भारत की गिर शेर परियोजना के तहत शेरों की आबादी को बढ़ावा दिया है - जो 1990 में 284 थी जो 2020 में बढ़कर 674 हो गई है।

भारत ने विश्व की पहली अंतर-महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी जीव स्थानांतरण परियोजना के माध्यम से भारत में चीता को पुनः स्थापित किया है।

भारत में 33 हाथी रिजर्व के साथ जंगली एशियाई हाथियों की अब तक की सबसे बड़ी संख्या है, अनुमानतः उनकी संख्या लगभग 30,000 यानि प्रजाति की जनसंख्या का लगभग 60 प्रतिशत है।

भारत में तेंदुओं की अनुमानित जनसंख्या 13,874 है, जो 2018 में इसी क्षेत्र में 12,852 तेंदुओं की तुलना में सकारात्मक स्थिर जनसंख्या को दर्शाती है।

गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पुनरुद्धार की प्रमुख परियोजना के रूप में मान्यता दी गई है, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों और उसकी सेवाओं के संरक्षण, पुनरुद्धार और विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत ने पहले ही 10 सितंबर, 2024 को राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजनाओं के तहत अपने राष्ट्रीय लक्ष्य तय किए हैं और हाल ही में कोलंबिया के कैली में संपन्न सी.बी.डी. सी.ओ.पी. के दौरान जैव विविधता पोर्टल पर 31 अक्टूबर, 2024 को सम्मेलन में अपनी राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) भी प्रस्तुत की है। राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य और कार्य योजनाएं दोनों ही कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक विविधता रूपरेखा (केएमजीबीएफ) के तहत निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ पूरी तरह से संरेखित हैं। केएमजीबीएफ को राष्ट्रीय परिस्थितियों, प्राथमिकताओं और क्षमताओं के अनुसार लागू किया जाना है। भारत की राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना (एनबीएसएपी) में स्थलीय और समुद्री क्षेत्रों की रक्षा, क्षतिग्रस्त इको-सिस्टम को बहाल करने और प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ शिकारी प्रजातियों के प्रबंधन के माध्यम से जैव विविधता के खतरों को कम करने की परिकल्पना की गई है। भारत, प्रजातियों के संरक्षण, संसाधनों के सतत उपयोग, विखंडन को कम करने के लिए वन्यजीव गलियारों और जैव विविधता शासन में सामुदायिक भागीदारी पर जोर देता है। भारत ने जीएचजी उत्सर्जन को कम करने के लिए नवंबर 2022 में यूएनएफसीसीसी में अपनी दीर्घकालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति (एलटी-एलईडीएस) प्रस्तुत की है, जिसमें देश के लिए रणनीतिक निम्न स्तरीय-उत्सर्जन विकास बदलाव पर प्रकाश डाला गया है। एलटी-एलईडीएस को वैश्विक कार्बन बजट के एक समान और उचित हिस्से के भारत के अधिकार के दायरे में तैयार किया गया था, जो जलवायु न्याय का व्यावहारिक कार्यान्वयन है। रणनीति में विकास के अनुरूप बिजली प्रणालियों में निम्न कार्बन विकास, एकीकृत, कुशल, समावेशी निम्न-कार्बन परिवहन प्रणाली का विकास, शहरी डिजाइन में अनुकूलन को बढ़ावा देना, भवनों में ऊर्जा और सामग्री-दक्षता और टिकाऊ शहरीकरण, उत्सर्जन से विकास को अलग करने और एक कुशल, अभिनव निम्न कार्बन उत्सर्जन औद्योगिक प्रणाली के विकास को बढ़ावा देना, सीओ 2 निष्कासन और सम्बन्धित इंजीनियरिंग समाधान प्रमुख रूप से शामिल हैं। 2023 में यूएनएफसीसीसी को भेजी गई अनुकूलन रिपोर्ट में जलवायु जोखिमों और चुनौतियों के अनुकूलन के लिए उठाए गए कदमों और उसके लिए भविष्य की रणनीति की रूपरेखा दी गई है। भारत ने खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा उपयोग दक्षता और जल प्रबंधन से लेकर एकीकृत दृष्टिकोण विकसित किया है, जिसका उद्देश्य उचित नीतियों और पहलों के माध्यम से इन मुद्दों को एक साथ संबोधित करना है। यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने 28 नवम्बर को राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

देश में हीटवेव की खतरनाक दर

जलवायु परिवर्तन के कारण, वैश्विक स्तर पर वार्षिक तापमान में वृद्धि हो रही है और इसका प्रभाव भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में हीटवेव की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता में दृष्टिगोचर होती है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट में भी यह परिलक्षित होती है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, सामान्य तौर पर, उत्तरी मैदानी इलाकों और मध्य भारत को कवर करने वाले हीट कोर जोन में हीटवेव की आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। हाल ही में आईएमडी ने हीटवेव पर एक मोनोग्राफ प्रकाशित किया जो भारत में हीटवेव पर व्यापक जानकारी प्रदान करता है। भारत सरकार द्वारा आने वाले वर्षों में हीटवेव के कारणों में कमी लाने के लिए राज्यों की मदद से अनेक पहलें की गई हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) और जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना (एसएपीसीसी) इन प्रमुख पहलों में शामिल हैं। इसके अलावा, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन और आपदा-प्रतिरोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन जैसी पहलों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाई है। भारत विकास के लिए निम्न-कार्बन वाली रणनीतियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार सक्रिय रूप से उनका अनुसरण कर रहा है।

आईएमडी, देश के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के समन्वय के साथ, निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणालियों में सुधार लाने की दिशा में कई कदम उठा रहा है, जिससे हीटवेव सहित चरम मौसम के दौरान जीवन और संपत्ति के नुकसान में कमी लाने में मदद मिली है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से हीटवेव की स्थिति वाले 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान (एचएपी) को संयुक्त रूप से लागू किया गया है। हीटवेव के कारण पिछले वर्ष फसल उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से विभिन्न क्षेत्रों में कुछ सब्जियों ने खाद्य मुद्रास्फीति पर दबाव डाला। सरकार ने आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए समय पर उचित कदम उठाए। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, आवश्यक खाद्य वस्तुओं के बफर स्टॉक को सुदृढ़ करना और आवधिक रूप से उसे खुले बाजार में पहुंचाना, निर्दिष्ट दुकानों में चावल, गेहूं का आटा और दालों जैसी वस्तुओं की सब्सिडी के साथ खुदरा बिक्री, शुल्कों को युक्तिसंगत बनाकर आवश्यक खाद्य वस्तुओं के आयात को आसान बनाना, अधिरोपण/संशोधन के माध्यम से जमाखोरी रोकना और स्टॉक सीमाओं की निगरानी करना शामिल है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना बहुत हद तक कमजोर वर्गों को खाद्यान्न मूल्य के दबाव से बचाती है।

महाराष्ट्र उन 23 राज्यों में शामिल है जहां हीट एक्शन प्लान (एचएपी) पहले ही लागू किए जा चुके हैं। हीटवेव पूर्वानुमान और चेतावनी की जानकारी केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्थानीय सरकारी निकायों सहित सभी हितधारकों को प्रदान की जाती है। आईएमडी हीटवेव सहित चरम मौसम की घटनाओं के लिए तैयार रहने के लिए आम लोगों और आपदा प्रबंधन प्राधिकारियों के लिए विभिन्न दृष्टिकोण/पूर्वानुमान/चेतावनियां जारी करता है। अलर्ट जारी करते समय, अपेक्षित गंभीर मौसम के प्रभाव को उजागर करने और आसन्न आपदा मौसम घटना के लिए की जाने वाली कार्रवाई के बारे में आपदा प्रबंधन संकेत देने के लिए एक उपयुक्त रंग कोड का उपयोग किया जाता है। आईएमडी तैयारी के लिए काफी समय पहले आवश्यक चेतावनियां और सलाह जारी करता है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय हीटवेव तैयारी बैठकों की एक श्रृंखला गर्मी के मौसम की शुरुआत से बहुत पहले आयोजित की जाती है, जिसमें मौसम के दौरान समय-समय पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित होती हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) पूरे देश में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं को समान रूप से लागू करता है और आईएमडी हीटवेव के बारे में चेतावनी सहित मौसम और जलवायु संबंधी पूर्वानुमान और चेतावनियां जारी करता है। आईएमडी समन्वित रूप से पूर्व चेतावनी सेवाओं में सुधार लाने के लिए अनुसंधान केंद्रों के साथ सहयोग करता है। यह अपने उत्पाद तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारी विभागों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों सहित विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों को संलग्न करता है। हीटवेव तैयारी बैठकों और कार्यशालाओं के माध्यम से अन्य सरकारी एजेंसियों और जलवायु विशेषज्ञों के साथ नियमित परामर्श और समन्वय किया जाता है। मौसम आधारित और मासिक दृष्टिकोण विभिन्न हितधारकों की तैयारियों का आकलन करने का अवसर प्रदान करते हैं और लघु से मध्यम श्रेणी के पूर्वानुमान के बाद एक विस्तारित सीमा जमीनी स्तर की कार्रवाई का अनुमान लगाती है। यह जानकारी केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने 27 नवम्बर को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

iTVoice® all things tech.

India's Premier IT Magazine & First Daily Tech News OTT

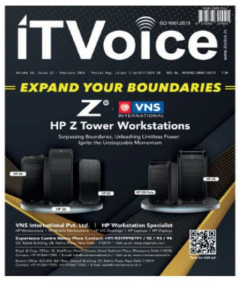

Magazines & Newspapers

iV

Highest Digital Presence

www.itvoice.in

Daily Tech News & Podcasts

Contact for Print & Digital Marketing

+91 141 4014911
info@itvoice.in

ICPL
www.icpljpr.com

Professional IT Support

Domain & Hosting
Web Development
Customized Software Solution
Web Operation
Client / Server Management
Network Maintenance
Service Desk Support
Customized IT Support Services
Dealing in all Major Brands

Informatic Computech Private Limited

Jaipur - Rajasthan (Ph.) +91-141-2280510 md@icpljpr.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक तरूण कुमार टांक के लिये महारानी प्रिन्टर्स प्लाट नं. 17, माँ वैष्णो देवी नगर, कालवाड़ रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 52/121, वीरतेजाजी रोड, मानसरोवर, जयपुर (राज.) से प्रकाशित। सम्पादक-तरूण कुमार टांक Email: mahanagarstambh@gmail.com